भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3343

(20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत पक्के आवासों का निर्माण

3343. श्री हरभजन सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में पक्के आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पंजाब के लोगों के लिए पक्के आवास संस्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बुनियादी सुविधाओं के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवासों (पिछले चरण यानी 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य सहित) के निर्माण के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसमें से राज्यों द्वारा 3.90 करोड़ से अधिक आवासो को मंजूरी दी गई है और दिनांक 16.03.2026 तक 2.98 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल आवंटित लक्ष्यों, राज्य द्वारा स्वीकृत मकान और निर्मित आवासों का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	स्वीकृत	निर्मित
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
2	असम	9,36,026	8,62,516	1,42,559
3	बिहार	13,11,390	12,08,747	3,13,693
4	छत्तीसगढ़	14,66,082	12,70,921	7,01,969
5	गोवा	0	0	0
6	गुजरात	2,99,011	2,28,608	1,16,249
7	हरियाणा	77,058	47,070	12,334
8	हिमाचल प्रदेश	92,364	69,038	35,640
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10	झारखंड	6,42,016	3,46,884	35,632
11	केरल	1,97,759	44,600	2,012
12	मध्य प्रदेश	19,75,026	15,29,906	5,05,688
13	महाराष्ट्र	29,96,724	27,87,765	4,11,603
14	मणिपुर	7,000	5,046	0
15	मेघालय	0	0	0
16	मिज़ोरम	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0
18	ओडिशा	1,24,304	1,02,424	67,445
19	पंजाब	63,985	36,985	10,599
20	राजस्थान	7,80,342	7,17,705	1,89,743
21	सिक्किम	0	0	0
22	तमिलनाडु	2,10,623	17,147	15,701
23	त्रिपुरा	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	70,834	44,113	42,809
25	उत्तराखंड	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0	0	0
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0
28	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
29	दमन और दीव	0	0	0
30	लक्षद्वीप	0	0	0

31	पुदुचेरी	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	684	505	104
33	कर्नाटक	7,02,731	3,25,875	13,477
34	तेलंगाना	0	0	0
35	लद्दाख	0	0	0
	कुल	**1,19,53,959**	**96,45,855**	**26,17,257**

 # आवाससॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विशेष परियोजनाओं के आकडें को छोड़कर)

(ग) & (घ) जी, हां। पंजाब राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 63,985 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से राज्य द्वारा 36,985 आवासों को मंजूरी दी गई है और दिनांक 16.03.2026 तक 10,599 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, पंजाब राज्य को राज्य में हाल ही के बाढ़/भारी वर्षा को ध्यान मे रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएमएवाई-जी के तहत विशेष परियोजनाओं के तहत 36,703 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य भी आवंटित किया गया है।